

रोहतक में युवक की गोली मारकर हत्या

बदमाशों ने करीब बीस राउंड की फायरिंग, दिनेश उर्फ गोगा नाम के युवक की मौत



एजेंसी (हि.स.)
रोहतक

शहर के दिल्ली बाइपास के समीप एक निजी अस्पताल के बाहर दो बदमाशों ने सोमवार की देर शाम एक युवक की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए, इसी बीच सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया।
शुरुआती जांच में सामने आया कि गैंगवार के चलते वारदात हुई है। पुलिस के अनुसार सोमवार देर शाम को दिल्ली

समाज की मजबूती-बुजुर्गों के अनुभव, संस्कार और आशीर्वाद से ही संभव : महीपाल ढांडा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़
हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने कहा कि जो समाज अपने बुजुर्गों को सम्मान देता है, वही समाज प्रगति की राह पर आगे बढ़ता है। उन्होंने महाराजा सूरजमल के आदर्शों को वर्तमान समय में प्रासंगिक बताते हुए कहा कि उनके बताए मार्ग पर चलकर समाज शिक्षा, संगठन और सेवा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त कर सकता है। ढांडा जाट समाज के महान योद्धा एवं दूरदर्शी शासक महाराजा सूरजमल जाट के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कैथल में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्ग हमारी विरासत, हमारी धरोहर थीम पर आधारित कार्यक्रम में समाज के बुजुर्गों, युवाओं, शिक्षाविदों तथा गणमान्य नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग

कुरुक्षेत्र के नैसी गांव में तर्कशील मेले का आयोजन

एजेंसी (हि.स.)
चंडीगढ़
तर्कशील सोसाइटी हरियाणा गांव नैसी जिला कुरुक्षेत्र में तर्कशील मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन जसप्रीत कौर व कर्मजीत ठसका ने किया।
पंजाबी फिल्मों एवं टी.वी. के कलाकार एकरत सिंह के नेतृत्व में चंडीगढ़ स्कूल ऑफ ड्रामा की टीम ने नाटक ' रंगी ' और ' ब्लाकी राम ' नाटक तथा कोरियोग्राफी ' मजदूर दी लुट ' व देश नू चल्लो ' प्रस्तुत किए। तर्कशील जादूगर 'फरियाद सन्याना' व 'राम प्रसाद' की टीम ने ' चमत्कारों का पदार्फाश ' शो में विभिन्न मैजिक ट्रिक्स दिखाए व उनकी व्याख्या भी प्रस्तुत की। उन्होंने इस के साथ ही चमत्कारों में न फंसेना की अपील की और बताया कि दुनिया में चमत्कार के नाम पर आम जन की लूट की जाती है। बलजीत भारती महासचिव ने तर्कशील सोसाइटी का परिचय देते हुए संस्था की 23 शतों की

29 विभागों के 271 कैडरों के लिए ऑनलाइन

तबादला अभियान का दूसरा चरण जल्द

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़
हरियाणा सरकार मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी -2025 के तहत ऑनलाइन तबादला अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत करने जा रही है। इस चरण में 29 विभागों एवं बोर्डों के 271 कैडरों को शामिल किया जाएगा।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस प्रक्रिया को सुचारु रूप से लागू करने के लिए संबंधित विभागों ने इंद्रा हरियाणा पोर्टल पर कार्यरत नियमित कर्मचारियों के डाटा का प्रारंभिक अपडेट शुरू कर दिया है। सभी कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने यूजर आईडी से लॉग-इन कर अपनी प्रोफाइल में दर्ज विवरण को ध्यानपूर्वक जांच लें। यदि किसी कर्मचारी की जानकारी में कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है, तो उसे तुरंत पोर्टल पर दर्शाए गए संबंधित प्राधिकारी/चेकर से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज जमा कराने होंगे, ताकि सही जानकारी दर्ज की जा सके।

20 फरवरी तक इंद्रा हरियाणा पोर्टल पर अपनी जानकारी अपडेट करें कर्मचारी

डाटा का सही और समय पर अपडेट होना जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर सेवा अवधि, मेरिट अंक और पात्रता निर्धारित की जाएंगी। उन्होंने आगे बताया कि आवश्यकतानुसार कर्मचारियों को न्यायालय के आदेश, मृत्यु प्रमाण पत्र, अधिकृत मेडिकल बोर्ड चंडीगढ़, रोहतक, हरियाणा/दिल्ली/चंडीगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेज) द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र, यूडीआईडी प्रमाण पत्र और अन्य सरकारी दस्तावेज संबंधित चेकर को प्रस्तुत करने होंगे। प्रवक्ता ने बताया कि सभी कर्मचारी मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी-2025 और उसके संशोधनों को भली-भांति पढ़ें तथा 20 फरवरी, 2026 तक अपनी प्रोफाइल का सत्यापन और अपडेट सुनिश्चित करें।

फरीदाबाद : फैक्ट्री में आग से दो पुलिसकर्मियों समेत एक दर्जन झुलसे

फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर-24 स्थित एक फैक्टरी में सोमवार शाम को भीषण आग लगने से दो पुलिसकर्मी और 10 अन्य लोग झुलस गए। आग इतनी तेजी से फैली कि फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया। घायलों को तुरंत बादशाह खान अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।फायर विभाग और पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फैक्ट्री में सीएनसी मशीन से स्टील की प्लेट काटने का काम होता है। शाम करीब चार बजे प्लेट काटते समय एक चिंगारी केमिकल से भरे ड्रम में चली गई। कर्मचारियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन इससे ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री में फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंचीं। आग बुझाने के दौरान तेल से भरे ड्रमों की मौजूदगी से आग और भडक गई। वहीं शॉर्ट सर्किट को भी आग का एक कारण बताया गया है, लेकिन प्रारंभिक जांच में सीएनसी मशीन से निकली चिंगारी और केमिकल ड्रम में ब्लास्ट मुख्य वजह लग रही है। झुलसे हुए लोगों में मनोज, लुकमान, अनीश, राकेश, विपिन, रविंदर व अन्य शामिल हैं। दो पुलिसकर्मी भी आग बुझाने और बचाव कार्य में शामिल होने के दौरान झुलस गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और फैक्ट्री मालिक से पूछताछ की जा रही है। फायर विभाग और पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आग पर अब पूरी तरह काबू पालिया गया है। औद्योगिक क्षेत्रों में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त दिशा निर्देशों की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है।
--



के रुपमें हुई।
मौके पर पहुंचे डीएसपी रवि खुंडिया ने बताया कि अभी तक यह पड़ताल कर रही है। सीन आफ क्राइम की टीम ने भी घटना स्थल का निरीक्षण
कौन थे और इस हत्या के पीछे कारण क्या रहे हैं।
पुलिस मामले की गहनता से जांच
पड़ताल कर रही है। सीन आफ क्राइम की टीम ने भी घटना स्थल का निरीक्षण

हिसार : बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा व सम्मान से निर्धारित होती किसी भी राष्ट्र की प्रगति : जनरल वत्स

एजेंसी (हि.स.)
हिसार
महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में इरिया हरियाणा चैप्टर के तत्वावधान में आयोजित फीटल इको कार्डियोग्राफी रिफ्रेशर कोर्स सोमवार को सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए वरिष्ठ रेडियोलॉजिस्ट, प्रोफेसर, चिकित्सकगण, शोधार्थी एवं प्रतिभागियों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। यह आयोजन मातृ-शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति चिकित्सा जगत की प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से अभिव्यक्त करता है।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनरल डॉ. डीपी वत्स रहे। उनके साथ विंशा अतिथि, वरिष्ठ शिक्षकों की तथा प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति ने समारोह की गरिमा को और बढ़ाया। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक दीप



प्रज्वलन से हुआ, जो ज्ञान, सेवा और चिकित्सा के उज्ज्वल संकल्प का प्रतीक है। समारोह के दौरान समाज के प्रति चिकित्सा समुदाय की जिम्मेदारी को रेखांकित करते हुए मुख्य अतिथि ने सभी उपस्थित चिकित्सकों, विद्यार्थियों और प्रतिभागियों को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के समर्थन में शपथ दिलाई। शपथ में कन्या भ्रूण हत्या के विरोध, बालिकाओं की शिक्षा को

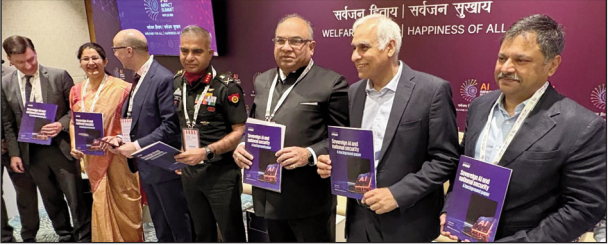
बढ़ावा देने, लैंगिक समानता स्थापित करने तथा समाज में सम्मानजनक वातावरण निर्मित करने का संकल्प लिया गया। मुख्य अतिथि जनरल डॉ. डीपी वत्स ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसकी बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान से निर्धारित होती है। उन्होंने चिकित्सा समुदाय की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि डॉक्टर केवल उपचरकर्ता ही नहीं,

एआई के दुरुपयोग से बढ़ सकती हैं डीपफेक व साइबर हमलों की चुनौतियां : अजय सिंघल

एजेंसी (हि.स.)
चंडीगढ़

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने सोमवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई एम्पेक्ट समिट 2026 में राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में ह्रासोवरन एआईईह की आवश्यकता पर अपने विचार व्यक्त किए। शिखर सम्मेलन का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केपीएमजी इंडिया के सहयोग से किया गया।

डीजीपी सिंघल ने कहा कि इंटरनेट और मोबाइल क्रांति के बाद अब एआई एक अत्यंत शक्तिशाली तकनीक के रूप में उभर रहा है, जो शासन और सुरक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने की क्षमता रखता है। यह केवल कार्यों को तेज करने का माध्यम नहीं, बल्कि शासन, सुरक्षा और समाज की संरचना



को पुनर्परीभाषित करने वाली परिवर्तनकारी शक्ति है। उन्होंने कहा कि यदि एआई का विकास स्वदेशी, सुरक्षित और विश्वसनीय आधार पर नहीं हुआ, तो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी प्रणालियां जोरिम में पड़ सकती हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने एआई के पाँच स्तर—ऊर्जा, निप्स, अवसररचना, मॉडल और एप्लीकेशन—का उल्लेख करते हुए कहा कि केवल एप्लीकेशन स्तर पर आत्मनिर्भर होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि बिजली, निप्स, डेटा और सर्वर सहित पूरी तकनीकी व्यवस्था

सीनियर सैकेण्डरी की 25 तथा सैकेण्डरी की 26 फरवरी से संचालित होंगी वार्षिक परीक्षाएं

सैकेण्डरी व सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक/मुक्त विद्यालय) के एडमिट कार्ड कल से होंगे लाईव



(शैक्षिक/मुक्त विद्यालय) वार्षिक परीक्षाओं के प्रवेश-पत्र (एडमिट कार्ड) कल से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर लाईव होंगे। सभी विद्यालय मुखिया बोर्ड वेबसाइट ६६६.२.ई.एल.एल पर अपने यूजर आई.डी. व पासवर्ड से लॉगिन करके आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए विद्यालय में अध्ययनरत परीक्षार्थियों के प्रवेश-पत्र का रंगीन प्रिंट आउट ए-4 साईज पेपर पर डाउनलोड करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि यदि परीक्षार्थी के विवरणों में कोई त्रुटि है तो तुरंत बोर्ड कार्यालय में सम्पर्क करते हुए शुद्धि से सम्बंधित मूल दस्तावेज एवं वांछित शुद्धि शुल्क सहित बोर्ड कार्यालय में उपस्थित होकर शुद्धि करवा सकते हैं। सभी परीक्षार्थी प्रवेश पत्र पर दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन

अमृत भारत स्टेशन योजना में कालावाली स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य आरंभ

एजेंसी (हि.स.)
सिरसा

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत उत्तर-पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल के 15 स्टेशनों के आलावा सात स्टेशनों पर भी पुनर्विकास कार्य होगा। सिरसा जिले के कालावाली रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास का कार्य आरंभ हो चुका है और लगभग छह प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार स्टेशन भवन के समरूप में बड़े स्तर पर सुधार कार्य, स्टेशन की ओर आने-जाने वाले मार्ग में प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग प्रावधान का कार्य, बाउंड्री वॉल, सकुलेंटिंग एरिया में सौंदर्यीकरण, दोपहिया, चौपहिया वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग सुविधा, बुकिंग ऑफिस रिटायरिंग रूम आदि में सुधार, नए टॉयलेट ब्लॉक्स का कार्य होगा। लगभग आठ करोड़ 76 लाख रुपये की लागत से होने वाले पुनर्विकास कार्यों में उपरोक्त कार्यों के अलावा सौंदर्य वर्धन के लिए एलइडी लाइटिंग, तथा दीवारों पर आर्टवर्क भी किया जायेगा। स्टेशन का मुख्य प्रवेश द्वार अत्यंत आकर्षक बनाया जाएगा,



जिसकी छत पर स्थानीय कला एवं संस्कृति का समन्वय करते हुए कलाकारों द्वारा आकर्षक पेंटिंग की जाएगी। इन सभी सुविधाओं का दिव्यांगजनों तक पहुंच बनाने के लिए उपयुक्त साइनेज भी लगाया जाएगा। इसके अलावा यात्री सूचना प्रणाली में सुधार हेतु के कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड, मस्ट्री लाइन डिस्प्ले बोर्ड्स, सिंगल लाइन डिस्प्ले बोर्ड, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, बड़े एलइडी स्क्रींस तथा जीपीएस आधारित डिजिटल क्लॉक भी लगाया जाएगा।

स्टेशन की प्रकाश व्यवस्था, सुगम, निर्बाध एवं निरंतर तकनीकी रेल कार्यों के संचालन के लिए हरित ऊर्जा उत्पादन सोलर ऊर्जा प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन

संक्षिप्त-समाचार

सोनीपत: 17 फरवरी से 11 अप्रैल तक होगी सीबीएसई परीक्षाएं, धारा 163 लागू

सोनीपत। सोनीपत में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जिला में 17 फरवरी से 11 अप्रैल तक आयोजित होनी वाली सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं के महेनजर जिलाधीश सुशील सारवान ने परीक्षा केंद्रों पर बाहरी हस्तक्षेप की रोकथाम, सार्वजनिक शांति एवं सौहार्द में व्यवधान उत्पन्न न हो इसलिए सोमवार को जिला में धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए। परीक्षाओं को आयोजन प्रातः 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक किया जाएगा। जिलाधीश के आदेशनुसार सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के हथियार जैसे तलवार, गंडासी, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, चाकू आदि लेकर चलने पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास मोबाइल फोन लेकर अनावश्यक रूप से घूमने तथा फोटोस्टेट की दुकानों के संचालन पर भी परीक्षा आदि के दौरान प्रतिबंध लगाया गया है। जिलाधीश सुशील सारवान ने आगजन से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें और परीक्षा कार्य में सहयोग दें। आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

इन् नू ने 28 फरवरी तक बढ़ाई नए दाखिले और पुन: पंजीकरण की अंतिम तिथि

चंडीगढ़। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इणून्) ने विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र कार्यक्रमों में प्रवेश जनवरी 2026 सत्र के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 फरवरी, 2026 कर दी है। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है, ताकि वे अभ्यर्थी जो किसी कारणवश निर्धारित समय सीमा में आवेदन नहीं कर पाए थे उन्हें एक और अवसर मिल सके, जो विद्यार्थी किसी अन्य महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में नियमित पाठ्यक्रम (रेगुलर मोड) में अध्ययनरत हैं, वे भी इणून् से एक अतिरिक्त डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रम में प्रवेश लेकर अपने करियर विकल्पों का विस्तार कर सकते हैं। इससे उन्हें दो अलग-अलग विषयों में गहन ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। उन्होंने बताया कि पुनः पंजीकरण कराने वाले विद्यार्थियों को 200 रुपये विलंब शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय ने सभी पात्र विद्यार्थी निर्धारित तिथि के भीतर आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना पुनः पंजीकरण सुनिश्चित करें, ताकि आगे किसी प्रकार की शैक्षणिक असुविधा से बचा जा सके।

एडवोकेट जनरल, हरियाणा एवं उच्च न्यायालय कार्यालय में प्रवेश हेतु ऑनलाइन विजिटिंग पास अनिवार्य

चंडीगढ़। हरियाणा के महाधिवक्ता तथा उच्च न्यायालय कार्यालय में प्रवेश को सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन विजिटिंग पास प्रणाली लागू की जा रही है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अब हरियाणा के महाधिवक्ता तथा उच्च न्यायालय के कार्यालय में कार्यालयों से संबंधित किसी भी आधिकारिक कार्य अथवा किसी केस या सुनवाई के लिए आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों एवं संबंधित व्यक्तियों को एलएमएस पोर्टल (3३३२२:/1/२९८.३३३.ल्ल) के माध्यम से पूर्व में ऑनलाइन विजिटिंग पास बनवाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन विजिटिंग पास के संबंध में आवेदक के पास अपना एम्प्लॉई आईडी कार्ड अनिवार्य होना चाहिए, गेट पास के प्रिंटआउट को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से सत्यापित करवाना होगा तथा पास जारी होने के उपरंत संबंधित कार्यालय से उसका सत्यापन करवाना आवश्यक होगा। प्रवक्ता ने बताया कि इस नई प्रणाली के माध्यम से कार्यालय में प्रवेश प्रक्रिया को अधिक संगठित, सुरक्षित एवं डिजिटल बनाया गया है, ताकि कार्य निष्पादन में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित की जा सकेगी।

से रोका गया है तो ऐसे विद्यालय/परीक्षार्थी बोर्ड कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में व्यक्तिगत तौर पर वांछित साक्ष्यों/दस्तावेज सहित उपस्थित होकर अपना प्रवेश-पत्र जारी करवा सकते हैं।

उन्होंने आगे बताया कि यदि किसी दिव्यांग परीक्षार्थी को लेखक की सुविधा लेनी है तो परीक्षा केन्द्र के मुख्य केन्द्र अधीक्षक/केन्द्र अधीक्षक द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्रामाणिक दिवांग प्रमाण पत्र/वस्त्रक उर्फ़ की जांच करने उपरान्त दिव्यांग परीक्षार्थी को परीक्षा आरंभ होने से एक घण्टा पूर्व लेखक उपलब्ध करवाया जाएगा, इसके अतिरिक्त बोर्ड कार्यालय में सहायक सचिव द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्रामाणिक दिव्यांग प्रमाण पत्र/ की जांच करने उपरान्त दिव्यांग परीक्षार्थी को परीक्षा आरंभ होने से एक दिन पूर्व लेखक उपलब्ध करवाया जाएगा।

संपादकीय

भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका केवल वित्तीय लेनदेन तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इन्हें सामाजिक और आर्थिक विकास के वाहक के रूप में देखा जाता रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का विस्तार, छोटे बचतकर्ताओं को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना इनकी प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में एक ऐसी प्रवृत्ति सामने आई है जिसने बैंकिंग व्यवस्था के इस सामाजिक चरित्र पर सवाल खड़े किए हैं। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बीते पाँच वर्षों में न्यूनतम शेष राशि बनाए न रखने पर ग्राहकों से लगभग साढ़े आठ हजार करोड़ रुपये तक जुमाना वसूला है। यह स्थिति केवल राजस्व संग्रह का मामला नहीं है, बल्कि इससे यह बहस भी जन्म लेती है कि क्या यह नीति वास्तव में ग्राहक हितों और वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों के अनुरूप है। न्यूनतम बैलेंस रखने की शर्त मूल रूप से बैंकिंग संवा‍लन को व्यवस्थित बनाए रखने और प्रशासनिक लागत को संतुलित करने के लिए लागू की गई थी। बैंक खातों की देखरेख, लेनदेन की प्रक्रिया, सुरक्षा उपायों और तकनीकी संरचना पर खर्च करते हैं, जिसके कारण शुल्क और जुमानों को एक वित्तीय साधन के रूप में देखा गया। लेकिन समय के साथ यह व्यवस्था ऐसे वर्गों पर बोझ बन गई जिनकी आय अस्थिर है। असंगठित क्षेत्र के कामगार, छोटे किसान, दैनिक मजदूरी करने वाले लोग और निम्न आय वर्ग के ग्राहक अक्सर नियमित रूप से खाते में निर्धारित राशि बनाए रखने में सक्षम नहीं होते। नतीजतन, वे बार-बार जुमानों चुकाने के लिए विवश हो जाते हैं, जो उनकी आर्थिक स्थिति को और कमजोर कर सकता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण विरोधाभास भी सामने आता है। सरकार और बैंकिंग संस्थाएँ वित्तीय समावेशन के लिए खाते खोलने को प्रोत्साहित करती हैं, लेकिन यदि उन्हीं खातों पर जुमानों का बोझ बढ़ता है तो ग्राहक

बैंकिंग प्रणाली से दूरी बना सकते हैं। कई मामलों में देखा गया है कि खाते निष्क्रिय हो जाते हैं या ग्राहक केवल आवश्यक लेनदेन तक ही सीमित रहते हैं। यह प्रवृत्ति वित्तीय समावेशन के दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए चुनौती बन सकती है। इस मुद्दे का एक और पहलू पारदर्शिता और जानकारी की उपलब्धता से जुड़ा है। कई ग्राहकों को यह स्पष्ट नहीं होता कि उनके खाते पर न्यूनतम बैलेंस की क्या शर्तें लागू हैं, जुमानों की दर कितनी है और उससे बचने के विकल्प क्या हैं। बैंकिंग शर्तों की जटिल भाषा और सूचना की कमी के कारण उपभोक्ता अनजाने में अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करते रहते हैं। वित्तीय साक्षरता के अभाव में यह समस्या और गहरी हो जाती है। इसलिए विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि ग्राहकों को स्पष्ट और सरल भाषा में जानकारी उपलब्ध कराई जाए तथा जागरूकता कार्यक्रमों को मजबूत किया जाए। हालाँकि बैंकिंग क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शुल्क और जुमानों की व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करना भी सरल नहीं है। बैंकिंग ढाँचे को बनाए रखने के लिए लागत आती है, और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी प्रतिस्पर्धात्मक, वातावरण में कार्य कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म, साइबर सुरक्षा और ग्राहक सेवा के लिए निवेश आवश्यक है। लेकिन प्रश्न यह है कि इन खर्चों का संतुलन किस प्रकार स्थापित किया जाए ताकि बैंक भी टिकाऊ रहें और ग्राहकों पर अनावश्यक भार भी न पड़े। डिजिटल बैंकिंग के विस्तार ने इस बहस को नया आयाम दिया है। ऑनलाइन लेनदेन और मोबाइल बैंकिंग के बढ़ते उपयोग से बैंकिंग लागत में कमी आने की संभावना व्यक्त की जाती है। साथ ही, शून्य-बैलेंस खातों जैसी पहले यह दशार्तें हैं कि वैकल्पिक मॉडल संभव है। यदि तकनीकी प्रगति के माध्यम से सेवाएँ सस्ती और सुलभ बनाई जा सकती हैं, तो जुमानों की नीति में भी लचीलापन लाने की गुंजाइश बनती है। उदाहरण के तौर पर, आय या खाते के उपयोग के आधार पर शुल्क

संरचना में भिन्नता लाई जा सकती है या कमजोर वर्गों को छूट दी जा सकती है। नीतिगत स्तर पर नियामक संस्थाओं और सरकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। बैंकिंग शुल्क से संबंधित नियमों की समय-समय पर समीक्षा और ग्राहक संरक्षण के उपाय आवश्यक हैं। यदि जुमानों की राशि अव्यवस्थित प्रतीत होती है, तो इसके सामाजिक प्रभाव का आकलन किया चाहिए। जनप्रतिनिधियों और उपभोक्ता संगठनों द्वारा इस विषय को उठाया जाना भी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भी आत्ममंथन की आवश्यकता है। उनकी स्थापना का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं था, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी निभाना भी था। यदि उनकी नीतियाँ कमजोर वर्गों के लिए असुविधाजनक बनती हैं, तो ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो सभी वर्गों के लिए समान रूप से अनुकूल हों। अंततः, यह बहस एक अवसर भी प्रदान करती है-ऐसी नीतियों को विकसित करने का अवसर जो बैंकिंग क्षेत्र को अधिक पारदर्शी, लचीला और जलनमुखी बना सके। जब बैंकिंग सेवाएँ सहज और भरोसेमंद होंगी, तभी वित्तीय समावेशन का लक्ष्य पूर्ण रूप से साकार हो सकेगा और आम नागरिक स्वयं को आर्थिक प्रणाली का सक्रिय हिस्सा महसूस करेंगे।

बांग्लादेश की नई सरकार को यूनुस के किरदार को समझना होगा

बीते दो वर्ष में बांग्लादेश ने राजनीतिक भूचाल देखा है। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी एशियाई प्रधानमंत्री को देश से भागना पड़ा। अब बांग्लादेश की नई गाथा के बाद एक नया कूटनीतिक अध्याय शुरू होगा। आम चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने कड़े स्वर में कहा कि सत्ता सંभालते ही उसका पहला बड़ा एजेंडा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रत्यर्पण होगा। अब सवाल सिर्फ़ कानूनी नहीं बल्कि भारत-बांग्लादेश संबंधों की दिशा तय करने वाला भी है चूँकि बीते लंबे समय से हसीना को लेकर भारत-बांग्लादेश के अलावा पूरी दुनिया की निगाह है कि आखिर शेख हसीना को लेकर अलाा अध्याय क्या होगा। बीएनपी की स्थायी समिति के सदस्य सलाहुद्दीन अहमद ने शुक्रवार को स्पष्ट कहा कि उनकी पार्टी भारत से औपचारिक रूप से शेख हसीना को ट्रायल के लिए बांग्लादेश प्रत्यर्पित करने का आग्रह करेगी। उनका कहना है कि यह मामला दोनों देशों के संबंधित मंत्रालयों के बीच तय कानूनी प्रक्रिया के तहत सुलझाया जाना चाहिए।

बीएनपी का तर्क है कि हसीना के कार्यकाल में हुए कथित दमन और भ्रष्टाचार के मामलों की निष्पक्ष सुनवाई जरूरी है। पार्टी ने भारत से सहयोग की उम्मीद जताई है लेकिन यह भी स्पष्ट कर दिया है कि न्यायिक प्रक्रिया से पीछे हटने का सवाल नहीं उठता। बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी की बड़ी जीत के बाद पार्टी नेता तारिक रहमान देश की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। इसके



योगेश कुमार सोनी (हि.स)

साथ ही दो दशक बाद बांग्लादेश की सत्ता में बीएनपी की वापसी हो रही है। इसका असर भारत पर भी होगा। बांग्लादेश के 13वें राष्ट्रीय चुनाव में बीएनपी ने 300 में से 212 सीटों पर रिकॉर्ड जीत हासिल कर बहुमत हासिल किया है। जमात-ए-इस्लामी गठबंधन को मात्र 77 सीटें हासिल हुई हैं। अन्य दलों का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा। र्व सत्ताधारी अवामी लीग को इस चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी गई।

अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना की 15 साल पुरानी सरकार गिर गई थी जिसके बाद से देश राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा के दौर से गुजरा। अब बांग्लादेश सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वहां बढहाली व गुंडागर्दी को कैसे नियंत्रित करेगी। दुनिया ने खुली आंखों से देखा कि किस तरह देश के प्रधानमंत्री की भी जान सुरक्षित नहीं है। गुंडागर्दी का तांडव ऐसा हुआ कि हसीना के निजी अंगवस्त्रों के साथ फोटो सोशल मीडिया पर डाले गए। मोहम्मद यूनुस ब्रांड के रूप में जाने जाते हैं। उनकी वैश्विक पहचान एक सामाजिक उद्यमी और नागरिक समाज के नेता के रूप में रही है। उनकी यह घोषणा कि थी वह चुनाव के बाद सत्ता में

नहीं रहेंगे लेकिन आज बांग्लादेश की सरकार को यूनुस की कितनी आवश्यकता है और क्या वह उनके किरदार व अनुभव का इस्तेमाल करके अपने आप को सशक्त करने का प्रयास करेगी। यह अहम सवाल है। सरकार को यूनुस का फायदा यह मिल सकता है कि उनकी साख सभी नेताओं से बहुत मजबूत मानी जाती है।

संभावना जताई जा रही है कि चुनाव के बाद यूनुस फिर से सामाजिक विकास, गरीबी उन्मूलन और फिनटेक आधारित वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस तरह उनका भविष्य प्रत्यक्ष राजनीति से दूर, लेकिन राष्ट्रीय पुनर्निर्माण से जुड़ा रह सकता है। टाइम मैगजीन ने बुधवार को वर्ष 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें मोहम्मद यूनुस को जगह मिली है।

पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने पहली बार लिखा था कि यूनुस बांग्लादेश को मुश्किलों से बाहर निकाल रहे हैं और मानवाधिकारों को बहाल कर रहे हैं। बहरहाल, अब बांग्लादेश को स्वयं को लेकर अपनी सकारात्मक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। चूँकि जितना नुकसान बीते कुछ समय में हुआ है उसकी भरपाई करना बेहद मुश्किल है। सरकार का नया स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि वह अपनी छवि को सुधारते हुए सभी के साथ चले और देश की जनता में अपना विश्वास बनाए रखे।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

श्रम सहिताएं : एक नई दृष्टि



प्रो बीजू वर्के

जरूरतों का सामना करना पड़ता था। श्रमिक और खास तौर से असंगठित कामगार आम तौर पर वैधानिक संरक्षण के दायरे से बाहर थे। श्रम सहिताओं ने अनुपालन की पिछली जटिल प्रणाली को समरूप परिभाषाओं, डिजिटल प्रक्रियाओं और विस्तारित दायरे से सरल बनाया है।

सम्मानजनक कार्य सिद्धांतों का अनुपालन: सुधारों में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के सम्मानजनक कार्य सिद्धांतों को शामिल किया गया है। इन कार्य सिद्धांतों में उच्च गुणवत्ता वाले रोजगारों का सृजन, श्रमिक अधिकारों और समानता का संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा और संवाद शामिल है।

अनुपालन का सरलीकरण: पुरानी प्रणाली में अत्यधिक कागजी कार्रवाई, निरीक्षणों पर अतिनिर्भरता और कमजोर अनुपालन जैसी खामियां थीं। नई सहिताओं में अनुपालन प्रणालियों को सुचारु बनाने के साथ ही उल्लंघनों को रोकने के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की गई है।

संवहनीय विकास लक्ष्यों के साथ तालमेल: ये सहिताएं श्रमिक अधिकारों को मजबूत कर, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करते हुए तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देकर संवहनीय विकास लक्ष्य (एसडीजी) 8 को आगे बढ़ाती हैं। इसके अलावा ये एसडीजी 1,3,5 और 10 को हासिल करने में भी सहायक हैं।

सुदृढ़ीकरण और सामंजस्य: भारत के श्रम कानून ऐतिहासिक तौर पर विभाजित तथा परिभाषाओं की बहुलता और सख्त अनुपालन व्यवस्थाओं से ग्रसित थे। नियोक्ताओं को एकदूसरे से मिलती-जुलती अनेक नियामक



डॉ शैलजा त्रिपाठी

प्रावधानों, व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज और वैकल्पिक कार्य व्यवस्थाओं के औपचारीकरण के जरिए भविष्य की कार्य संबंधी चिंताओं का निराकरण किया गया है।

सहिताओं की मुख्य विशेषताएं और उनका प्रभाव:

वेतन सहिता, 2019: यह सहिता पिछले चार कानूनों को एकीकृत करती है और रमजदूरीर की एक समान परिभाषा तथा 'राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी' की अवधारणा पेश करती है। यह व्यापक और अधिक सुसंगत वेतन सुरक्षा सुनिश्चित करती है, समय पर भुगतान को अनिवार्य बनाती है, और समान पारिश्रमिक के नियम को सुदृढ़ करती है, जिससे आय सुरक्षा मजबूत होती है और विवादों में कमी आती है।

औद्योगिक संबंध सहिता, 2020: यह सहिता मजदूर संगठनों, औद्योगिक विवादों और स्थायी आदेशों को नियंत्रित करने वाले कानूनों को एक साथ लाती है। यह विवाद समाधान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती है, निश्चित समय-सीमा निर्धारित करती है और हड़ताल, कामबंदी तथा छंटनी से जुड़े नियमों को तर्कसंगत बनाती है। जहाँ यह नियोक्ताओं को परिचालन के लिए लचीलापन प्रदान करती है, वहीं सामूहिक सौदेबाजी और कानूनी समाधान के लिए सुरक्षा उपायों को भी बरकरार रखती है।

सामाजिक सुरक्षा सहिता, 2020: यह सहिता संगठित क्षेत्र से आगे जाकर सुरक्षा के दायरे का विस्तार करके एक बड़े बदलाव का संकेत देती है। इसके अंतर्गत गिंग कामगारों, प्लेटफॉर्म के जरिये काम करने वाले श्रमिकों को

भविष्य निधि, बीमा, मातृत्व लाभ और वृद्धावस्था सुरक्षा से संबंधित वैधानिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने का प्रावधान किया गया है।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति (ओएसएच) सहिता, 2020: यह ओएसएच सहिता सुरक्षा से संबंधित कई कानूनों को एक एकीकृत ढांचे में समाहित करती है। यह कार्यस्थल सुरक्षा मानदंडों का मानकीकरण करती है, नियामक निरीक्षण को मजबूत करती है और सभी क्षेत्रों में इसे लागू करने में सुधार करती है।

आगे की राह क्या है ?

बी. बी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा नए श्रम कानूनों के बारे में नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि इन सहिताओं ने बेहतर भविष्य के प्रति सकारात्मक उम्मीद जगाई है। जहाँ 64% श्रमिकों का मानना ​​है कि सहिताओं के लागू होने से आय सुरक्षा बढ़ेगी, वहीं नियोक्ताओं ने भी निश्चित अवधि के रोजगार अनुबंधों (64%) और कार्यस्थल सुरक्षा (73%) को लेकर इसी तरह के भाव व्यक्त किए हैं। दोनों ही हितधारक इन सहिताओं को एक ऐसे साधन के रूप में देखते हैं जो दोनों पक्षों के अनुभवों को बेहतर बनाएगा।

चारों श्रम सहिताएं भारत के श्रम शासन में एक ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रतीक हैं। पुराने पड़ चुके कानूनों को एकीकरण, सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार और नियोक्ताओं के लचीलेपन तथा श्रमिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाकर, इन सुधारों का उद्देश्य एक अधिक समाधान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती है, निश्चित समय-सीमा निर्धारित करती है और हड़ताल, कामबंदी तथा छंटनी से जुड़े नियमों को तर्कसंगत बनाती है। जहाँ यह नियोक्ताओं को परिचालन के लिए लचीलापन प्रदान करती है, वहीं सामूहिक सौदेबाजी और कानूनी समाधान के लिए सुरक्षा उपायों को भी बरकरार रखती है।

(लेखक, प्रो. बीजू वर्के आईआईएम अहमदाबाद में प्रोफेसर और डॉ शैलजा त्रिपाठी वेजईडेक्टर हैं)

सृजन, सुविधा और नई संस्कृति

कहा जाता है कि हर नई तकनीक अपने साथ सुविधा लेकर आती है, पर कुछ तकनीक धीरे-धीरे हमारी सोच और आदतों को भी बदल देती हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आज ऐसे ही मोड़ पर खड़ी है। उसने लिखने की गति बढ़ाई है, उसे आसान और सुलभ बनाया है, पर उसी अनुपात में उसने सृजन के अर्थ को घुंघला भी किया है। अब प्रश्न यह नहीं रह गया कि ‘लिखा कितना अच्छा है’, बल्कि यह बन गया है कि ‘लिखा किसने है’ और किस तरह लिखा है।’ जब किसी लेख, कविता या विचार को पढ़ते हुए यह बोझ होता है कि वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा रचा गया है, तो पाठक के भीतर कुछ टूट-सा जाता है। शब्द सधे हुए होते हैं, भाव भी उपयुक्त लगते हैं, पर कहीं एक रिक्तता रह जाती है। जैसे सुंदर शरीर हो, पर उसमें प्राण न हो। रचना का वह जादू, जो लेखक और पाठक के बीच एक अदृश्य संबंध बनाता है, अनावक समाप्त हो जाता है। यह केवल सौंदर्य का नहीं, विश्वास का भी प्रश्न है।

समस्या यह नहीं है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता लिख सकती है। समस्या यह है कि वह लिखते समय मनुष्य होने का भ्रम रचती है। वह अनुभव की नकल करती है, पीड़ा की भाषा बोलती है, प्रेम और करुणा के मुहावरे दोहराती है। उस बिना कभी असफलता, भय या

दुविधा से गुजरे। जब ऐसी सामग्री किसी मनुष्य के नाम से प्रस्तुत की जाती है, तो वह तकनीकी सहायता नहीं रह जाती; वह बौद्धिक नकल का रूप ले लेती है। यह नकल कोई नई बात नहीं है। हमारी शिक्षा व्यवस्था लंबे समय से इस मानसिकता को पोषित करती रही है कि अंक सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं, प्रक्रिया नहीं। परीक्षा में नकल करके उत्तीर्ण होना, दूसरों की उत्तर पुस्तिकाओं से विचार उठाना, और फिर उसी सफलता का गर्वपूर्वक प्रदर्शन—यह सब समाज में किसी न किसी रूप में स्वीकार्य रहा है। आज नवी प्रवृत्ति कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से नई शकल में सामने आई है। अंतर केवल इतना है कि अब नकल अधिक चमकदार, अधिक विश्वसनीय और अधिक सुरक्षित दिखाई देती है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पन्न सामग्री की एक पहचान बन चुकी है—भाषा की दृष्टि से निर्दोष, सरचना में संतुलित, और भावनात्मक रूप से ‘उचित’। पर यही परिपूर्णता उसे संदिग्ध भी बनाती है। क्योंकि वास्तविक सृजन प्रायः परिपूर्ण नहीं होता। उसमें झिझक होती है, दोहराव होता है, कभी-कभी असंगति भी होती है। सच्चा लेखक अपने ही विचारों से जूझता है, अपनी ही सीमाओं से संघर्ष करता है। उस संघर्ष की खंघा शब्दों में दिखाई



डॉ. सत्यवान सौरभ (हि.स)

देती है, और वही रचना को जीवंत बनाती है।

आज सामाजिक माध्यमों और अंकोंय मंचों पर सामग्री का बाढ़ है। हर विषय पर, हर दृष्टिकोण से, तुरंत लेख उपलब्ध हैं। इस भीड़ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक तीव्र यंत्र की तरह काम करती है, जो पहले से मौजूद हजारों विचारों को जोड़कर एक नया पैकेज बना देती है। यह पैकेज उपयोगी हो सकता है, जानकारी पूर्ण हो सकता है, पर क्या वह दृष्टि दे सकता है? क्या वह गंभीर प्रश्न प्रेय का है। यदि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एक औजार की तरह उपयोग किया जाए—शोध, संपादन या भाषा-सुधार के लिए—और यह स्पष्ट कर दिया जाए कि इसमें यंत्र की सहायता ली गई है, तो यह ईमानदारी है। पर जब पूरी रचना यंत्र द्वारा तैयार की जाए और लेखक का नाम किसी मनुष्य का हो, तो यह धोखा है। यह पाठक के साथ भी अन्याय है और सृजन की परंपरा के साथ भी। अकर यह तर्क दिया जाता है कि डिजिटल परिणाम ही महत्त्वपूर्ण है, तरीका नहीं। ढ़ पर यही तर्क नकल को भी वैध ठहराता है। यदि तरीका अप्रासंगिक होता, तो शिक्षा, प्रशिक्षण और अभ्यास का कोई अर्थ न रह जाता। सृजन केवल परिणाम नहीं है, वह एक प्रक्रिया भी है। लिखते समय जो सोच विकसित होती है, जो आत्मसंघर्ष होता है, वही लेखक को गढ़ता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता उस प्रक्रिया को बीच में ही काट देती है।

यह कहना भी आवश्यक है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वयं में शत्रु नहीं है। हर तकनीक की तरह उसका मूल्य उसके उपयोग में निहित है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब सुविधा, सृजन का स्थान लेने लगती है। जब लेखक बनने के स्थान पर ‘सामग्री

उत्पादक’ बनने की होड़ लग जाती है। जब पहचान मेहनत और अनुभव से नहीं, बल्कि उत्पादन की मात्रा से तय होने लगती है। भविष्य में संभवतः दो प्रकार के लेखन स्पष्ट रूप से दिखेंगे। एक, जो तेज होगा, चमकदार होगा, हर जगह उपलब्ध होगा—और शीघ्र भुला दिया जाएगा। दूसरा, जो धीमा होगा, सीमित होगा, कभी-कभी असुविधाजनक भी होगा—पर टिकेगा। क्योंकि वह किसी मनुष्य द्वारा चुकाई गई कीमत के साथ लिखा गया होगा।

पाठक भी धीरे-धीरे इस अंतर को समझने लगेंगे। लेखक का मूल्य उससे साहस से आंका जाएगा—उस साहस से, जिसे किसी यंत्र से उधार नहीं लिया जा सकता। अंततः प्रश्न कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नहीं, हमारी ईमानदारी का है। सृजन सदैव कठिन रहा है और रहेगा। जो उसे अत्यधिक आसान बना देता है, वह अकसर उसे खोखला भी कर देता है। इसलिए आज, इस तकनीकी कोलाहल के बीच, सबसे आवश्यक प्रतिरोध यही है कि हम लिखते समय यह स्मरण रखें—शब्द केवल जोड़ने के लिए नहीं होते, जीने के लिए होते हैं। और जीवन की सच्ची अनुभूति की नकल कोई भी यंत्र, चाहे वह कितना ही कुशल क्यों न हो, पूर्ण रूप से नहीं कर सकता।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਆਰ ਕਾਂਗਰੇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਦਲਦਲ ਮੈਂ ਧਕੇਲਾ, ਅਬ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਬਨਾ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਹਮਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰ ਚਿਟ੍ਰੇ ਕਾ ਕਲਾਂਕ ਹਟਾਨੇ ਕਾ ਵਾਦ ਕਿਆ ਥਾ, ਜੋ ਹਮ 'ਧੁਕੁਦ ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਵਿਰੁਕੁਦ' ਅਭਿਆਨ ਕੇ ਮਾਧਯਮ ਸੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਹ ਮਾਨ



ਸਿਟੀ ਦਰ্পਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਮੋਗਾ

ਮੋਗਾ ਮੇਂ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੇਂਸ ਕਮੇਟੀ (ਵੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਕੇ ਸ਼ਾਪਥ ਗ੍ਰਹਣ ਸਮਾਰੋਹ ਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਕੇ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰੀਯ ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਮੁਖ਼ਯਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਹ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇ 'ਧੁਕੁਦ ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਵਿਰੁਕੁਦ' ਅਭਿਆਨ ਕੇ ਤਹਤ ਸਪੁਸ਼ਟ ਆਰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਤੇ ਹੁਏ ਕਹਾ ਕਿ ਜਹਾਂ ਸ਼ਿਰੋਮਣਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਆਰ ਕਾਂਗਰੇਸ ਨੇ ਰਾਜ਼ਯ ਕੋ ਨਸ਼ਾ ਮੇਂ ਡੁਬੋ ਦਿਆ, ਵਹੀਂ 'ਆਪ' ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਭਰਪਾई ਕੇ ਲਿਏ ਨਸ਼ਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਰ ਕਿਸੀ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰੰਵਾਓਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਆਪ' ਪ੍ਰਮੁਖ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਂ ਪਹਲੀ ਬਾਰ ਕਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾ ਕੋ ਬਚਾਨੇ ਕੀ ਬਜਾਯ ਉਨਕੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰੰਵਾਓਂ ਕੀ ਹੈ। ਉਨਹੋਨੇ 2,000 ਕਿਲੋ ਸੇ ਅਧਿਕ ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਕੁਰਾਮਦਗੀ, ਕੁਛੇ ਸੀਦਾਗਰੋਂ ਕੋ ਜੇਲਾਂ ਮੇਂ ਡਾਲਨੇ ਆਰ ਉਨਕੇ ਮਹਲਨੁਮਾ ਘਰਾਂ ਪਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਨੇ ਕਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਤੇ ਹੁਏ ਕਹਾ ਕਿ ਧੁਕੁਦ ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਵਿਰੁਕੁਦ ਅਭਿਆਨ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸ਼ਤਰ ਪਰ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਮਨੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਉਨਹੋਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਲੋਗਾਂ ਕੀ ਸਚੇਤ ਕਰਤੇ ਹੁਏ ਕਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਿਛਲੀ ਸਚਕਾਰੇਂ ਸੱਤਾ ਮੇਂ ਆਓਂ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਕੀ ਦਲਦਲ ਮੇਂ ਜਾਨੇ ਸੇ ਕੋਓਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਮੁਖ਼ਯਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਹ ਮਾਨ ਨੇ ਵੇਹਰਪਾਯਾ ਕਿ ਆਪ ਕੀ ਸਰਕਾਰ 'ਧੁਕੁਦ ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਵਿਰੁਕੁਦ' ਅਭਿਆਨ ਕੇ ਤਹਤ ਪੰਜਾਬ ਪਰ 'ਚਿਟ੍ਰੇ' ਕੇ ਦਾਗ ਕੋ ਮਿਟਾਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਪੂਰੀ ਤਰਹ ਵਚਨਬੁਧ ਹੈ। ਉਨਹੋਨੇ ਜੋਰ

ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰਛ਼ ਕਾ 27ਵਾਂ ਦਿਨ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 516 ਸਥਾਨਾਂ ਪਰ ਕੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; 181 ਕਾਬੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੁਖ਼ਯ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਹ ਮਾਨ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਦੇਸ਼ੀਂ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਗਏਂ ਨਿਰਧਾਨਕ 'ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ' ਮੁਹਿਮ ਕੇ 27ਵੇਂ ਦਿਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਮੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੇ ਸਾਥਿਯਾਂ ਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਹਚਾਨੇ ਗਏ ਆਰ ਮੈਪ ਕਏ ਟਿਕਾਨਾਂ ਪਰ 516 ਛਾਪੇਮਾਰਿਆਂ ਕੀ।ਜਾਨਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ - ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਨਾਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਏਕ ਨਿਰਧਾਨਕ ਜੰਗ ਝੜ 20 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਕੋ ਡਾਧਰੇਕੁਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਗਈ ਥੀ। ਇਸਕੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂਂ ਫ਼ਰਾ ਏਂਟੀ ਗੈਂਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਏਫ) ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇ ਸਾਥ ਰਾਜ਼ਯ ਭਰ ਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰੰਵਾਹਿਯਾਂ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਹਿਮ ਕੇ 27ਵੇਂ ਦਿਨ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 181 ਯਕਤਿਯਾਂ ਕੋ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨਸੇ 2 ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕਏ। ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਮੁਹਿਮ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੇ ਅਬ ਤਕ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਏ ਯਕਤਿਯਾਂ ਕੀ ਸੰਖ਼ਯਾ 9,442 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ 67 ਯਕਤਿਯੋਂ ਵਿਰੁਕੁਦ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰੰਵਾਹੀ ਕੀ ਗਈ, ਜਕਫਿ 139 ਯਕਤਿਯਾਂ ਕੀ ਤਸ਼ਦੀਕ ਕੀ ਗਈ ਆਰ ਪ੍ਰਭਾਤਾਭ ਕੇ ਬਾਦ ਉਨਕੋ ਛੋਡ ਦਿਆ ਗਯਾ।ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰੰਵਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 9 ਭਾਗੀਡੇ ਅਪਰਾਧਿਯਾਂ (ਪੀਐੱਓ) ਕੋ ਭੀ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿਆ ਹੈ। ਵਾੱਛ਼ਿਤ ਅਪਰਾਧਿਯਾਂ/ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਨਕਾਰੀ ਆਰ ਅਪਰਾਧ ਂਵ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤਿਵਿਧਿਯਾਂ ਕੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਲਾਗੂ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ਪਰ ਏਂਟੀ ਗੈਂਸਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 93946- 93946 ਪਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ।ਜ਼ਿਕੁਰਯੋਯ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਵਿਰੁਕੁਦ ਅਪਨੇ ਅਭਿਆਨ ਧੁਕੁਦ ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਵਿਰੁਕੁਦ ਕੀ 352ਵੇਂ ਦਿਨ ਭੀ ਜਾਰੀ ਰਖਤੇ ਆਜ 77 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਕੋ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ- ਕੇ ਉਨਕੇ ਕਛੇਜੇ ਮੇਂ ਸੇ 2 ਕਿਲੋ ਹੇਰੋਇਨ, 1345 ਨਸ਼ੀਲੀ ਗੋਲੀਆ/ ਕੈਸ਼ੂਲ ਆਰ 69,120 ਰੁਪਏ ਕੀ ਝਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਸਾਥ, ਸਿਰਫ਼ 352 ਦਿਨਾਂ ਮੇਂ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਏ ਗਏ ਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਕੀ ਸੰਖ਼ਯਾ 49, 841 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਜ਼ਿਕੁਰਯੋਯ ਹੈ ਕਿ ਕਰਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਏਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਕੀ 1.5 ਕਿਲੋ ਹੇਰੋਇਨ ਸਹਿਤ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਮੁਹਿਮ ਕੇ ਹਿਸ਼ਕੇ ਤੌਰ ਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਜ 16 ਯਕਤਿਯਾਂ ਕੋ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਆਰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇ ਲਿਏ ਰਾਜੀ ਕਿਆ ਹੈ।

इनोवेटिव प्रेजेंटेशन प्रतियोगिता में एआई और ग्रीन कंप्यूटिंग पर छात्रों की नवाचारी सोच ने बटोरी सराहना

सिटी दर्पण संवाददाता

चंडीगढ़। सेक्टर-32 स्थित गोस्वामी गणेश दत्त स्नातन धर्म कॉलेज के कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस विभाग के आईसीटी क्लब फीनिक्स की ओर से सोमवार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन कंप्यूटिंग-के बीच संबंध और उनके भविष्य को संभावनाओं पर छात्रों के रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रेरित करना था। इसमें विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण के साथ तकनीकी विकास को संतुलित करने से जुड़े विभिन्न नवाचारों और विचारों को प्रस्तुत किया। प्रतियोगिता



में विभाग के प्रतिभाशाली छात्रों की कई टीमों ने भाग लिया। प्रत्येक टीम को इस बात की पड़ताल करने का कार्य दिया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शक्ति का उपयोग पर्यावरणीय स्थिरता से समझौता किए बिना कैसे किया जा सकता है। आज के समय में बड़े डेटा सेटों के बढ़ते कार्बन फुटप्रिंट को लेकर तकनीकी उद्योग पर बढ़ती चिंता के बीच, प्रतिभागियों ने

सरटेनेबल इंटेलिजेंस और ऊर्जा-कुशल एप्लोारिदम डिजाइन जैसे विषयों पर नए और रचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता का मूल्यांकन फैकल्टी मेंबरस डॉ. हिमानी मिश्रल और डॉ. गरिमा श्रीवास्तव की ज्यूरी पैनल द्वारा किया गया। प्रतिभागियों को उनके तकनीकी ज्ञान, प्रस्तुति के दृश्यात्मक डिजाइन और जटिल विषयों को सरल तरीके से प्रस्तुत करने की



रही है। विपक्ष पर तंज कसते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, यदि मैं नियमित जांच के लिए अस्पताल भी चला जाऊं, तो वे मेरे और मेरे स्वास्थ्य के बारे में अफवाहें फैलाते हैं क्योंकि वे मुझसे और मेरे जनहितैषी दृष्टिकोण से ईर्ष्या करते हैं। मुख्यमंत्री सेहत योजना के बारे में जनता को गुमराह करने के लिए अफवाहों फैलाने पर विपक्ष की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, लोगों को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है, जो देश में अपनी तरह की पहली है। इस योजना के तहत पंजाब के प्रत्येक निवासी परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस चिकित्सा उपचार प्राप्त करने का अधिकार है। यह अत्यंत गर्व और संतोष की बात है कि पंजाब ऐसा व्यापक स्वास्थ्य कवरेज देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।

पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना जनता पर वित्तीय बोझ को काफी हद तक कम करेगी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा, यह ऐतिहासिक कदम राज्य के सभी परिवारों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। सभी सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और प्रत्येक अन्य नागरिक स्वास्थ्य कार्ड के पात्र हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस पहल से उन परिवारों को बड़ी राहत मिली है जिन्हें बीमारी की स्थिति में उपचार के लिए अपनी जेब से भारी खर्च करना पड़ता था।

उन्होंने कहा, हमने रंगला पंजाब को नशा मुक्त बनाने की यात्रा में आम जनता का सहयोग सबसे अधिक आवश्यक है। भगवंत सिंह मान ने कहा, पंजाब और पंजाबी हर युद्ध जीतने का गौरवरखते हैं, और अब नशे के खिलाफ यह युद्ध भी लोगों के सहयोग से जीता जाएगा।

पंजाब सरकार की ओर से लुधियाना के फर्जी स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई; मान्यता वापस लेने और आपराधिक शिकायत दर्ज करने की कार्रवाई शुरू

- हरजोत सिंह बैस ने शिक्षा प्रणाली में ईमानदारी और पवित्रता बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की
- शिक्षा मंत्री की ओर से जांच टीमों को अन्य सदिग्ध स्कूलों की जांच में तेजी लाने और जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश

थे, जिसके कारण पी.एस.ई.बी. ने उनके रोल नंबर हट कर दिए। उन्होंने बताया कि चार अन्य स्कूल जांच के अंतर्गत हैं क्योंकि पंजाब सरकार शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता करने वाली और परीक्षा में गड़बड़ियां करने वाली संस्थाओं पर शिकंजा कसने के लिए

हालांकि, भ्रामक जानकारी के खिलाफ चेतावनी देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री ने आगे कहा, कुछ पंजाब विरोधी ताकतें, जो नहीं चाहतीं कि राज्य के लोग ऐसी सुविधाओं का लाभ उठाएं, इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में जानबूझकर झूठ फैला रही हैं। ये भ्रामक बातें लोगों को योजना का लाभ लेने से हतोत्साहित करने के उद्देश्य से फैलाई जा रही हैं, जो पूरी तरह से अनुचित और अवांछनीय है।

भगवंत सिंह मान ने लोगों को इन ताकतों से सावधान रहने की चेतावनी दी, जो राज्य की प्रगति और जनता की समृद्धि को पटरी से उतारने की साजिश रच रही हैं।

पंजाब की छवि को हुए नुकसान पर दुःख व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि पंजाब ने कई उल्लूक खिलाड़ी, जर्नेल, शहीद और अन्य महान हस्तियां पैदा की हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इन ताकतों ने पंजाबियों को नशेड़ी कहकर पंजाब के नाम पर कफ़ी लगा दिया। उन्होंने कहा, जिन्होंने ये पाप किए हैं, उन्हें जनता सजा देगी, और आगे कहा कि, वे अपनी अवैध कमाई के बल पर अदालतों से सजा से बच सकते हैं, लेकिन जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि शिक्षकों और अभिभावकों दोनों को आगे आकर सामूहिक और समन्वित प्रयासों से नई पीढ़ी को बचाना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण राज्य में पासपोर्ट बनवाने वालों की संख्या कम

हुई है, क्योंकि पंजाब सरकार स्थानीय युवाओं को योग्यता के आधार पर रोजगार दे रही है। राज्य सरकार ने पूरे पंजाब में 63,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं, जिसके कारण लोग अब विदेश जाने की योजनाएं छोड़ रहे हैं। जहां राज्य सरकार जनता के कल्याण के लिए निरंतर काम कर रही है, वहीं विपक्ष अपने शासनकाल के दौरान केवल सफल योजनाओं में हिस्सेदारी चाहता था। विपक्षी नेतृत्व पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, ये वे शैतान हैं जो नशे और अपराधियों को संरक्षण देकर राज्य को बर्बाद करना चाहते हैं, जिसके कारण लोगों ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया है। अब ये सभी पंजाब-विरोधी ताकतें पंजाब को बर्बाद करने के लिए एकजुट हो गई हैं, और अब समय आ गया है कि पंजाबी भी एकजुट होकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएं। राज्य सरकार की जनहितकारी पहलों का उल्लेख करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, आज हर गाँव के अंतिम छोर तक पानी पहुँच रहा है, जबकि पहले नहर का पानी केवल संपन्न लोगों के खेतों तक ही सीमित रह जाता था।

उन्होंने कहा, अब 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है और किसानों को दिन के समय बिजली दी जा रही है, जिससे किसानों को काफी लाभ हुआ है। नशे के कारोबार में शामिल लोगों या नशा तस्करों की, समर्थन करने वालों के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई गई है।

संक्षिप्त-समाचार

सूर्य ग्रहण आज ,भारत में कहीं नही दिखेगा

जैतो। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण मंगलवार 17 फरवरी को लगने जा रहा है। यह ग्रहण भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजकर 26 मिनट लगेगा जो सायं 7 बजकर 57 मिनट तक रहेगा। यह जानकारी प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य दिवंगत पंडित कल्याण सरूप शास्त्री विद्यालंकार के पुत्र पंडित शिव कुमार शर्मा ने आज जैतो में दी। उन्होंने कहा कि यह ग्रहण अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका आदि में विशेष रूप से दिखाई देगा लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारत में कही दिखाई नहीं देगा जिस लिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि शरारों में कहा गया है कि जिस देश में ग्रहण दिखाई नहीं देता है वहां किसी भी राशि, राजनीतिक,आर्थिक व कारोबार पर तेजी – मंदी का शुभ व अशुभ प्रभाव नही पड़ता है।



मंदबुद्धि दलित युवा के साथ कुत्ते से कुकर्म करवाने के मामले में एस.सी.आयोग ने जालंधर देहाती के एस.एस.पी. से रिपोर्ट की तलब

चंडीगढ़। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने फिल्लौर में एक मंदबुद्धि दलित नौजवान के साथ कुत्ते से कुकर्म करवाने के मामले में सू मोतो नोटिस लिया है। इस सहबन्धित जानकारी देते पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन स. जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि फिल्लौर में एक मंदबुद्धि दलित नौजवान के साथ कुत्ते से कुकर्म करवाने के मामले में वीडियो वायरल हुई है और अखबारों में खबरें भी छपी है जिसका कमिश्न ने सू मोतो नोटिस लेते जालंधर देहाती के एस.एस.पी. से 19 फरवरी 2026 के रिपोर्ट तलब करी सुचना की रिपोर्ट दो पड़तों (एक असली और एक फोटो कापी) में डी.एस.पी भरत मसीह को निजी तौर पर कमीशन दफ़तर में पेश करने के आदेश दिए है।

बायोडायवर्सिटी के संरक्षण पर पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित



चंडीगढ़। सेक्टर-32 स्थित गोस्वामी गणेश दत्त स्नातन धर्म कॉलेज के जूलॉजी डिपार्टमेंट के द एरिसटोटल क्लब की ओर से पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का थीम हाज़मीन या पानी के इकोसिस्टम का संरक्षणह् था। प्रतियोगिता का विषय द एरिसटोटल क्लब की कोऑर्डिनेटर और जूलॉजी डिपार्टमेंट की हेड डॉ. इंदु मेहता ने चुना था। इसका मकसद ज़मीनी और पानी के इकोसिस्टम, दोनों पर फोकस करना था ताकि स्टूडेंट्स में बायोडायवर्सिटी और उसके बचाव के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़े। कार्यक्रम के जरिए विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने और उन्हें जैव विविधता के महत्व से जोड़ने की दिशा में सार्वक प्रयास किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न कक्षाओं के बीस विद्यार्थियों ने भाग लिया और अपनी रचनात्मकता व संवेदनशील सोच का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. अजय शर्मा ने इस प्रतियोगिता में द एरिसटोटल क्लब, फैकल्टी और वॉलंटियर्स की सक्रिय भूमिका की सराहना की।

समाधान शिविर में उठी ड्रेनेज की समस्या पर उपायुक्त सरबत

सेक्टर-21 पार्ट-3 में ड्रेनेज समस्या को एक सप्ताह में दूर करने के लिए निर्देश

सिटी दर्पण संवाददाता

पंचकूला

उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने सेक्टर-21 पार्ट-3 की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा उठाई गई ड्रेनेज की समस्या का सज्ञान लेते हुए नगर निगम को एक सप्ताह के भीतर समाधान कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त लघु सचिवालय के सभागार में हरियाणा सरकार के निदेशानुसार आयोजित समाधान शिविर में जिलावासियों की समस्याएं सुन रहे थे। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने अवगत कराया कि सेक्टर-21 पार्ट-3, पंचकूला में कुछ मकानों में ड्रेनेज पाइपलाइन की समस्या के कारण जलप्रभाव की स्थिति बनी रहती है, जिससे क्षेत्रवासियों को भारी असुविधा हो रही है। इस पर उपायुक्त ने नगर निगम अधिकारियों को मौके का निरीक्षण आगामी सोमवार तक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने आशवासन दिया कि समस्या का शीघ्र समाधान किया जाएगा।



श्रीमती ममता रानी ने गलत खतो में बिजली बिल का भुगतान होने की शिकायत रखी। उन्होंने बताया कि समान अकाउंट नंबर होने के कारण उन्होंने यूएचबीवीएन के बजाय डीएचबीवीएन के खाते में बिल जमा कर दिया। कई बार अनुरोध करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। उपायुक्त ने बिजली विभाग के संबंधित अधिकारी को 15 दिनों के भीतर त्रुटि को दूर कर समस्या का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गांव श्यामदू निवासी सतीश कुमार ने कनौली से श्यामदू तक मार्केटिंग बोर्ड द्वारा निर्मित सड़क में अनियमितताओं



श्रीमती ममता रानी ने गलत खाने की बिजली कायल का भुगतान होने की शिकायत रखी। उन्होंने बताया कि उसमान अकाउंट नंबर होने के कारण उन्होंने यूएचबीएफएन के बजयाय कर दिया। कई बार अनुरोध करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। उपानुक्त ने बिजली विभाग के सुर्हाइत अधिकारी को 15 दिनों के भीतर वृत्ति को दूर कर समस्या का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कानौनौ से श्यामदू तक मार्केटिंग बोर्ड द्वारा निर्मित प्रदायक ने अनियमितताओं

की सिकावत थी। उन्होंने बताया कि उद्देकावर ने सड़क के कुछ हिस्से में बिना पत्राचार के आधार तैयार किए सीधे मिट्टी पर टाइलें लगा दीं। उन्होंने गुणवत्ता बनाए रखने के लिए स्टीन डस्ट डालकर दोबारा टाइलें लगाई की मांग की। इसका प्र प्र उपायक ने पंचायती राज विभाग के कार्यकारी अभियंता को 5 दिनों में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निदेश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

समाधान शिबिर के दौरान गांव-चाकली बड़ी शेर भोज और गांव-दहलाना भोज दराडा, तहसील मोरनी के

नवाचारों ने कृषि भूमि को सिंचाई के बिना बिना वाटर टैंक के सिंचाई की मांग रखी। उपजोत्पादक ने समाज में मुद्रा स्थापना के अधिकारी, पंचकुला को इस संबंध में पूर्ण विवरण सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। समाधान शिविर में उपस्थित निम्न विभागों से संबंधित कुल 12 शिक्षिकायें सुनी गई। उपजोत्पादक ने सभी शिक्षिकायों को निर्देश दिए कि प्राप्त शिक्षिकायों का प्रथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण किया जाए, ताकि समाधानाचारिकों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।

उपजोत्पादक ने कहा कि समाधान शिविर आमजन की समस्याओं के

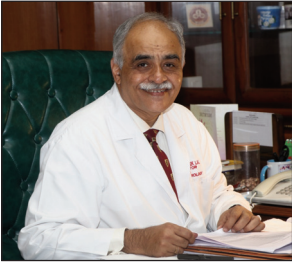
समाधान का प्रभावी माध्यम है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की मंशा यह है कि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अग्र-अलग कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें। इसी उद्देश्य से मुख्मंत्री ने निर्देशानुसार प्रत्येक सोमवार और बुधवार को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक समाधान शिविर आयोजित किया जाता है, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहते हैं। समय-समय पर मुख्मंत्री स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर शिक्षावर्गों की प्रगतियों की समीक्षा करते हैं। गणराष्ट्रकोडै लेते हैं। इस अवसर पर नागरिकों जा गुर्गाति, जिला विकास एवं परिवहन अधिकारी विशाल पराशर, नायब तहसीलदार हरदेव सिंह, स्वास्थ्यक मृदा संरक्षण अधिकारी रहूल बरनकोदिया, सीएम बिंडो के एमिर्नेट कर्मचारी सत्यम भारद्वाज सहित जनस्वास्थ्य अभियानिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, एचएसबीपीएमएडी, पुलिस, स्वास्थ्य, सिंचाई, ग्राम निगम और अन्य संबन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है तथा अनुसंधान एवं उर्वरक मंत्रालय, औषध विभाग, भारत सरकार के अधीन कार्य करता है, है, नई दिल्ली 16.02.2026 (सोमवार) को अपना स्थापना दिवस समारोह मनाया। संस्थान के निदेशक प्रो. दुलाल पांडा ने मुख्य अतिथि प्रो. अनिल कुमार त्रिपाठी, निदेशक, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली तथा विशिष्ट अतिथि डॉ. चंद्रशेखर नायर, कार्यकारी निदेशक एवं मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीईओ), मोलबायो इयामोनास्टिक्स एवं बंगेटेक लैब्स का स्वागत किया। प्रो. पांडा ने अपने संबोधन में कहा कि भारत को वैश्व स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, औषधियों एवं चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में वैश्विक प्रतिष्ठा के रूप में स्थापित करने के लिए अनुसंधान एवं उसके रूपांतरण (ट्रांसलेशन) में उत्कृष्टता प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे आयात पर निर्भरता कम की जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा मोहाली में बायोफार्मास्यूटिकल्स एवं प्रोद्योगिकी साइंसेज में दो नए स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रारंभ करने की घोषणा भी की। उन्होंने संस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत

परते हुए शैक्षणिक उपलब्धियों, अनुसंधान एवं अनुदानों, पेटेंट, प्लेसमेंट, समझौता ज्ञानों (एमओयू) तथा विभिन्न अनुदानों का विवरण दिया। उन्होंने बताया कि नाईपूर, एक्स्प्रेस नगर उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में अप्रत्याशित संस्थान है, जो सदैव उद्योग-उन्मुख शिक्षण कार्यक्रमों पर विशेष बल देता है। मुख्य रूप से विश्व प्री. ऑनल कुमार त्रिपाठी ने अहमदाबाद के पोर्टोडियल ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स : ऑपरच्युनिटीज एण्ड चैलेंजिज के विषय पर स्थापना दिवस व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने व्याख्यान में स्ट्रोक, हृदयवायु, कैंसर, मोटापा, मधुमेह आदि अनेक रोगों के उपचार में औषधीय पौधों एवं हर्बल दवाओं की उपयोगिता पर प्रकाश डाला तथा गुणवत्तापूर्ण हर्बल औषधियों के उत्पादन में मिलावट जैसी चुनौतियों को उल्लेख किया। विश्विनिटी डॉ. वंदरेश्वर नायर ने अपने संबोधन में कहा कि भारत को उपयोग में आने वाले उत्पादों का स्वदेशी निर्माण करना चाहिए तथा स्वदेशी वस्तुओं की उत्पादों के विकास के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सशक्त उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। रोश की मुख्य रणनीति अधिकारी सुश्री शीतल रंगनाथन ने संसर्गमिण्डिया, स्ट्रेंगिनिडिया, ट्यूबेरोसोइडिया (विषय पर विशेष व्याख्यान) का विवरण देते हुए अंतर्गत सामान्य वेबिनार प्रश्नोत्तरी, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

या साक्षर यौन उपजीवन झूठ आँनालाइन सहिलाओं की सुरक्षा विषय पर प्रतियोगिता सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जीतने वाले विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। स्मृति स्वरूप श्रीमती कृष्णा गुलाटी पुरस्कार (राशि 10,000/-) मेडिकल डिवाइसेस विभाग के श्री सोमनाथ कोठावडे वैभव को प्रदान किया गया। नेहा शर्मा मेमोरियल पुरस्कार आईसीओसी-नाईपर बेस्ट अचीवर अवार्ड औषधि प्रौद्योगिकी (बायोटेक) विभाग की सुश्री परनिता गुप्ता को प्रदान किया गया। वैभव परनितालिक सर्विसेस अवार्ड औषधीय प्रबंधन विभाग के श्री जितन, श्री सैय्यद अमन अजीज एवं श्री जेनेनु कुमार जैन को प्रदान किया गया। इस अवसर पर नाईपर ने रोश प्रोडक्सेस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड तथा विनायक अवार्ड ज्ञान रिसेच फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञान (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। नाईपर - मोहाली एवं रोश फार्मा लिमिटेड (जोकि रोश समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाय कंपनी है) के साथ व्यापक निर्माण एवं विकास, छात्र रामरश्मि, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की नियुक्ति तथा उद्योग-उन्मुख अत्यकालिक प्रतिक्रिया कर्मियों के संचालन के क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करने के लिए, जिनसे नाईपर- रोश मोहाली के विद्यार्थियों को उद्योग के लिए अधिक सक्षम एवं वैचार बनाया जा सके।

**पौजीआईएमइआर चंडीगढ़ में लंबे समय से पौडिंग
कार्डियक इमरजेंसी अब असलियत बनी**



कार्डियक इमरजेंसी के लिए खास तौर पर एक फोकस्ड क्लासिफिकेशन जरूरी है। कार्डियक सोसायटी तक, कार्डियाक इमरजेंसी में मरीजों को मेन इमरजेंसी विंग के जरिए ही भेजे जाते हैं। मरीजों को मेन इमरजेंसी विंग के जरिए ही भेजा जाता था, जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान और अस-पास के इलाकों से आने वाले ट्रॉमा, मेडिकल, सर्जिकल और गंभीर रूप से बीमार मामलों की बड़ी संख्या को देखाता था। राजधानी को संस्था को देखते हुए, ट्रांसपोर्टिव कार्डियक मामलों को अक्सर थ्रीड-थाइ वले सिस्टम में

काम करना पड़ता था, जिससे एक स्ट्रुई, स्पेशलाइज्ड रिसॉन्स की जरूरत पर जोर दिया गया। प्रो. विवेक लाल ने बताया कि पीजीआईएमईआर के डायरेक्टर के तौर पर उनके कार्यकाल की शुरुआत से ही, सिस्टम को आसान बनाने और मरीज-केंद्रित सुधारों को प्राथमिकता देने की कोशिश की गई थी। कार्डियोवैस्कुलर इमरजेंसी में टाइम बहुत जरूरी होता है। बचाया गया हर मिनट एक जान बचा सकता है। हमारा मकसद यह पक्का करना रहा है कि किसी भी कार्डियक मरीज का कामंती समय लॉजिस्टिक दिक्कतों की वजह से बर्बाद न हो। टीएम स्पिरिट की तारीफ करते हुए, पीजीआईएमईआर के डायरेक्टर ने कहा, डेडलाइन्ड कार्डियक इमरजेंसी कार्डियोलॉजिस्ट, इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन, एनेस्थेसिया, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और नर्सिंग सर्विसेज डिपार्टमेंट्स की कोशिशों से मुमकिन हो पाई है।



प्रकार एक ही मैद से अनेक प्रकार के व्यंजन बनते हैं, उसी प्रकार मूल तत्व एक ही रहता है। इसी तरह जल, बर्फ और भाप रूप बदलते हैं, पर उनका तत्व एक ही होता है। वैसे ही समस्त सृष्टि के कण-कण एक ही निराला परमात्मा विद्यमान है। सगुरु माता जी ने कहा कि मनुष्य जीवन अत्यंत अनमोल है क्योंकि इसी में परमात्मा की प्राप्ति संभव है। यह मनुष्य

पर निर्भर है कि वह अज्ञान में जीवन बिताए या जागरूक होकर प्रेम, क्षमा, सेवा और सद्भाव को अपनाए। सच्ची भक्ति भय, स्वार्थ या चतुराई से नहीं, ब्रह्मलिप्काम प्रेम से की जाती है।

मुञ्ज सेवा, सुमिरन और सत्संग से जुड़कर मानवता के गुणों को अपनाए। किसी को कष्ट पहुँचाया और क्षमा व प्रेम का व्यवहार रखे। परमात्मा का प्रेम अमिर-गरीब, उच्च-नीच या किसी भेदभाव में भेद नहीं करता; वह सभी परमात्मा रूप से बरसता है। भेटेड जौन के जेजोनल इंचांज श्री कुंवरपाल की ओर से जापान प्रत्येक श्रम यशस्वी ने विभिन्न स्थानों से आए हुए संत महात्माओं, थाई-लान्थां का धन्यवाद ज्ञापन किया तथा प्रशानसन से प्राप्त सहयोग हेतु प्रशानसन का भी आभार व्यक्त किया। निवेदित, समापन पत्र पंथस्थित चर्च ने एकत्व, प्रेम और मानवता के संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लिया।

कालका से कलेसर तक 7 दिवसीय ट्रेकिंग अभियान आरंभ, युवा बितायेंगे प्रकृति के साथ समय

सिटी दर्पण सवाददाता

पंचकुला

हरियाणा सरकार के युवा कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत आज से 7 दिवसीय ट्रेकिंग कैंप का शुभारंभ किया गया। यह विशेष ट्रेकिंग अभियान कालका से कलेसर तक कुल 153 किलोमीटर के लक्षित मार्ग पर आयोजित किया जा रहा है। इस ट्रेकिंग कैंप में हरियाणा के विभिन्न जिलों से आए छात्र भाग ले रहे हैं। युवा कल्याण संयोजक नंदर सिंह ने बताया कि यह ट्रेकिंग कैंप हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं को प्रकृति से जोड़ना, साहसिक गतिविधियों के प्रति प्रेरित करना तथा हरियाणा की प्राकृतिक एवं पर्वतीय सुंदरता से परिचित कराना है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से छात्र हरियाणा के प्राकृतिक परिवेश, पहाड़ों, वन्य जीवन और ऐतिहासिक स्थलों का प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। रैंज ऑफिसर संजय ने छात्रों को एक पेशेवर ट्रेकर की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने ट्रेकिंग के दौरान बर्ती जाने वाली सावधानियों, अनुशासन तथा टीम वर्क के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 153 किलोमीटर का यह ट्रेक दो राज्यों — हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरेगा। इस दौरान छात्र विभिन्न वनस्पति प्रजातियों, प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता का अवलोकन करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि ट्रेकिंग के



प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। रंज ऑफिसरों से संयोजन ने छात्रों को एक पेशेवर टैकर की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने टैकिंग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों, अनुशासन तथा टीका वक् के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 1530 घण्टा की क्लिकोमीटर का यह टैक दो रातों – हरियाणा और हिमाचल प्रदेश – से होकर गुजरेगा। इस दौरान छात्र विभिन्न वनस्पति प्रजातियों, प्राकृतिक सौंदर्य के अंगों और जैव विविधता का अवलोकन करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि टैकिंग के

दौरान छत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों का भ्रमण करेंगे, जिनमें मोरनी फोर्ट, पिंजौर गार्डन, समरोठा देवी मंदिर तथा आदी बंद्री मंदिर प्रमुख हैं। यह ट्रैकिंग कैंप में केवल युवाओं में साहस, नेतृत्व और अनुशासन की भावना का विकास करेगा, बल्कि उन्हें हरियाणा की समृद्ध प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर से भी जोड़ने का कार्य करेगा।

युवा कल्याण सयोजक नरेंद्र सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार के युवा कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत 16 फरवरी से 7 मार्च तक दो दिवसीय विशेष ट्रैकिंग

कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा , जिसमें प्रदेश के विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्राओं, विशेषकर हरियाणा के अध्ययनरत हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा उत्तर-प्रदेश के विद्यार्थियों को भी भाग लेना होगा । इस दौरान विद्यार्थियों को जलवायु परिवर्तन के विषय में जागरूक किया गया जाएगा तथा पर्यावरण संरक्षण के महत्त्व पर विस्तृत जानकारी दी गई । छात्रों पर प्राकृतिक परिवेश का अवलोकन किया, विभिन्न वनस्पतियों एवं जैव विविधता के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा एक लघु फिल्म 'कार्यगतिविधि में भी भाग लेंगे । इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाना, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करना तथा साहसिक गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरण के स्वच्छता का सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करना है ।

श्री अजय कुमार ने सुविधाएं सुदृढ़ करने के लिए निर्देश

सीजेएम-कम-सेक्रेटरी ने मोरनी क्षेत्र के लीगल एड क्लीनिकों का किया निरीक्षण

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के सीजेएम-कम-सेक्रेटरी श्री अजय कुमार ने आज मोरनी क्षेत्र में संचालित लीगल एड क्लीनिकों की कार्यप्रणाली एवं आधारभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्लीनिकों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं, स्थानीय लोगों की पहुँच तथा जमीनी स्तर पर प्रदान की जा रही विधिक सेवाओं की प्रभावशीलता का आकलन करना है। गांव भोज जव्याल स्थित लीगल एड क्लीनिक का निरीक्षण गांव की सरपंच सुश्री काजल की उपस्थिति में किया गया। श्री अजय कुमार ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर यह जानकारा प्राप्त की कि उन्हें क्लीनिक के माध्यम से विधिक सहायता एवं परामर्श सही प्रकार से मिल रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण एवं दूर-दराज क्षेत्रों में लीगल एड क्लीनिक स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य

यह सुनिश्चित करना है कि निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण विधिक सेवाएं समाज के जरूरतमंद एवं वंचित वर्ग तक पहुँचें। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि क्लीनिक वर्तमान में आंगनवाड़ी केन्द्र में संचालित हो रहा है, जहाँ आम लोगों की पहुँच अपेक्षाकृत कम है। इसे ध्यान में



यह सुनिश्चित करना है कि निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण विधिक सेवाएं समाज के जरूरतमंद एवं वंचित वर्ग तक पहुंचें। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि क्लीनिक वर्तमान में आंगनवाड़ी केंद्र में संचालित हो रहा है, जहां आम लोगों की पहुंच अपेक्षाकृत कम है। इसे ध्यान में

रखते हुए श्री अजय कुमार ने निर्देश दिए कि लीगल एड क्लिनिक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, भोज जब्याल में स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि यह अधिक सुलभ एवं प्रभावी स्थान है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग चिकित्सा सेवाओं के लिए आते हैं। मुख्य

चिकित्सा अधिकारी पंचकूला को भी निर्देश दिए गए कि पीएचसी भोज जजब्याल में क्लीनिक के सुचारु संचालन के लिए पर्याप्त स्थान एवं आवश्यक आधारभूत सामान उपलब्ध करवाया जाए। लोगों को कानूनी मामलों में सहायता एवं विभिन्न कल्याणकारी

योजनाओं तथा अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रत्येक रविवार को एक पैनल अधिवक्ता एवं एक पैरालीगल वालंटियर की नियुक्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को स्थानीय क्षेत्र में मुनादी (सार्वजनिक घोषणा) कराने

के निर्देश दिए गए ताकि ग्रामीणों को लक्षित/लाल उप कर्त्ताविक के समय एगरेटिव गैर-सहचारी के जाणाकारी मिल सके और अधिकारिक लोग इसका लाभ उठा सकें। श्री अजय कुमार ने मोरनी क्षेत्र के गांव भोगपुर स्थित एगरेटिव लाल उप कर्त्ताविक की श्री नरीशङ्क काला, जो आंगनवाडी केन्द्र में संचालित है। निर्देशिका के दौरान पाया गया कि कर्त्ताविक को कोई साइनबोर्ड नहीं लगाया गया है। इस पर उन्होंने डीडोप्री की को तुरंत उपयुक्त साइनबोर्ड लगवाने के निर्देश दिए ताकि आमजन आसानी से स्थान की पहचान कर सकें और विधिक सेवाओं का लाभ ले सकें।

उन्होंने कहा की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला लीगल एड क्लीनिकों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ कर उनके प्रभावी संचालन के लिए प्रतिबद्ध है ताकि विशेषकर ग्रामीण एवं दूर-दराज क्षेत्रों में सभी को न्याय सुलभ हो सके।

ग्रामीण पर्यटन क्षेत्र को प्रदर्शित किया। अनुभवों को उजागर किया गया, रिपोर्ट पर्यटन, फार्म स्टे और बेड एंड बैक, रिजर्वेशन, सरकार की प्रगतिशील पर्यटन नीतियों को प्राप्त है। पंजाब पर्यटन के प्रतिनिधियों ऐतिहासिक महत्व पर भी प्रकाश डाला है, जिनमें प्रमुख अकाल तख्त, तख्त साहिब शामिल हैं, जिससे यह धार्मिक बनता है। प्रस्तुति में पंजाब के जीवित धार्मिक समारोहों को भी रेखांकित किया में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

व्हर्लपूल ने पावरफुल कूलिंग के साथ 3डी कूल प्रो+ एसी रेंज लॉन्च की